



उच्च शिक्षा स्तर पर निजी संस्थानों के प्रभाव का अध्ययन

डॉक्टर दुर्गावती शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर गृहविज्ञान विभाग,

कृपालु महिला महाविद्यालय कुंडा प्रतापगढ़,

प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी- इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

Communicated : 18.06.2026

Revision : 20.07.2026
Accepted : 12.08.2026

Published: 30.09.2026

सारांश :

विगत कुछ वर्षों में भारत वर्ष के उच्च शिक्षा क्षेत्र के परिपेक्ष्य में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को आ रहा है। उच्च शिक्षा में हुए परिवर्तन और सुधारों से देश में तेजी से बढ़ते निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण कुछ वर्षों से बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई है। उच्च शिक्षा गहन ज्ञान और समझ प्रदान करती है। जिससे छात्रों के जीवन में विभिन्न क्षेत्र में ज्ञान के आयाम विकसित होते हैं। श्रेष्ठ ज्ञान और कौशल राष्ट्र के विकास में बहुमूल्य योगदान देते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान में दी जाने वाली गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा छात्रों के अन्दर गुणों का विकास करती है। शिक्षा की गुणवत्ता संस्थान के शिक्षक, बुनियादी ढांचा, शिक्षण पद्धति, और पाठ्यसहभागी गतिविधियों आदि पर निर्भर करती है। उच्च शिक्षण संस्थानों के निजीकरण ने छात्रों के रोजगार के अवसर परिणामों और आय के विभिन्न अवसरों को बढ़ाने और आर्थिक विकास प्रदान करने के लिए नई नीतियाँ और कार्यक्रमों का प्रारम्भ किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य कुण्डा क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों पर निजी संस्थानों के प्रभाव का अध्ययन करना है। डाटा चयन के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया। सर्वे विधि का प्रयोग करते हुए नमूने चयन के लिए 5 निजी शिक्षण संस्थानों और 5 सरकारी शिक्षण संस्थानों से 40 छात्रों को चुना गया। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों की शिक्षण व्यवस्था सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों से काफी हद तक श्रेष्ठ है।

प्रमुख शब्द- उच्च शिक्षा, निजीकरण, व्यक्तित्व विकास, संस्थान की गुणवत्ता

परिचय :

शिक्षा मानव विकास की आधार शिला है। शिक्षा के बिना मानव का विकास की कल्पना करना असम्भव है। मानव विकास ही किसी समाज की उन्नति और सम्पन्नता का वास्तविक प्रतीक माना जाता है। शिक्षा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तकनीकी प्रगति और आधुनिक जीवन स्तर के लिए विश्व भर में सुशिक्षित और कुशल लोगो की आवश्यकता है इसके अलावा शिक्षा को देश की आर्थिक उपलब्धि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानवीय संसाधनों का वास्तविक मूल्यवर्धन करने के साथ-साथ व्यवसाय सेवा, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों में धन और नेतृत्व क्षमता का विकास करना ही उच्च शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि इसे ही आर्थिक विकास और तकनीकी विकास का सूत्रधार माना जाता है। 90 वे दशक के शुरुआत तक उच्च शिक्षा का वित्त पोषण मुख्य रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता था।

लेकिन वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की बढ़ती माँग को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।

निजीकरण का साकारात्मक प्रभाव :

निजी उच्च शिक्षण संस्थान में देखा गया है कि ये संस्थाएं अक्सर बेहतर सुविधाएं आधुनिक पाठ्यक्रम और बेहतर शिक्षण विधियाँ प्रदान करते हैं। इन निजी संस्थानों में बच्चों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे छात्रों को अधिक विकल्प मिलते हैं। निजी संस्थानों में बाजार उन्मुख दृष्टिकोण से संस्थानों में दक्षता और नवीन शिक्षण विधियों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी से सरकारी शिक्षा प्रणाली पर वित्तीय दबाव कम होता है तथा रोजगार के अवसर विशेषकर विदेशी निजीकरण के साथ, रोजगार और आय पर साकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

निजीकरण का नाकारात्मक प्रभाव :-

निजीकरण होने से शिक्षा मंहगी होती जा रही हैं , जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। निजीकरण होने के कारण शिक्षा का व्यावसायिकरण होता जा रहा है। जिससे संस्थानों का ध्यान मानवीय और लोक तान्त्रिक मूल्यों के बजाय वित्तीय लाभ पर केन्द्रित होता जा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में निजीकरण होने के कारण पारदर्शिता जबाबदेही की समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही हैं तथा संस्थानों के निजीकरण होने के कारण आर्थिक लाभ की चाह में मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को नजर अंदाज किया जा रहा है।

उद्देश्य :

निजी एवं सरकारी उच्चशिक्षण संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता की तुलनात्मक अध्ययन करना

परिकल्पना :

निजी एवं सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता में अन्तर पाया जायेगा।

साहित्य समीक्षा :

बेड़ा ओबेरोन मनमीत (2017) ने भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण की आवश्यकता , प्रभाव और सुझाव, आंतरराष्ट्रीय शोध पत्र में उच्च शिक्षा के निजीकरण की आवश्यकता को समझाया गया है। भारत में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली है। उच्च शिक्षा का मिशन समानता, न्याय, गुणवत्ता, रोजगार समावेशिता शिक्षा हासिल करना है। धन की अनुपलब्धता की समस्या से निपटने के लिए नए संस्थानों की स्थापना के बजाय सरकार की प्राथमिकता मौजूदा संस्थानों की क्षमता का विस्तार करना और उच्च शिक्षा में नए शिक्षण संस्थानों को केवल निजी क्षेत्र में खोल कर शिक्षा का विकास किया जा सकता है।

ओझा चोंदनी (2018) भारत में उच्च शिक्षा पर गुणवत्ता आश्वासन के प्रभाव जैसे मुद्दे को उजागर करने की कोशिश की है। एक अन्य उद्देश्य कालेजो और विश्वविद्यालयों पर गुणवत्ता आश्वासन के प्रभाव के बारे में साहित्य की समीक्षा करना और इस गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया में विभिन्न पक्षों की भूमिका का पता लगाना है। एक और बात यह है कि विभिन्न परिभाषाओं और इससे सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करके गुणवत्ता का अर्थ समझना। अध्ययन गुणवत्ता और गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के बारे में है। बहुत कम संस्थान रेटिंग एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त कर रहे हैं इसलिए, गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रभाव शीलता के

महत्व के बारे में सभी हित धारकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

अन्नवेशा और दिलीप (2021) इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है, एक ओर उच्च शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक उच्च शिक्षा के लिए सरकारी वित्तीय सहायता धीरे-धीरे कम हो रही है इसलिए निजी क्षेत्र में लाभ केन्द्रित विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए निजी क्षेत्र में लाभ केन्द्रित विश्वविद्यालय तेजी से बढ़ रहे हैं। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों का तेजी से विकास भारत में उच्च शिक्षा के कई पहलुओं को विशेष रूप से उच्च शिक्षा में समानता और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है,

गिल (2021) ने निजी व्यवसायिक स्कूलों के लिए परिवर्तनकारी गुणवत्ता पैमाने को विकसित किए जिनमें महत्वपूर्ण आत्मविश्वास समस्या समाधान, कौशल, समग्र जागरूकता और निपुणता को प्रमुख गुणवत्ता आयामों के रूप में पहचाना गया है। वास्तविक शैक्षिक प्रतिबंधताओं के बिना मुख्य रूप से लाभ को अधिकतम करने के लिए स्थापित किए गए शोषणकारी संस्थाओं के बारे में चिन्ता बन रही है, जिससे छात्र के हितों की रक्षा और उच्च शिक्षा अखंडता को बनाए रखने के लिए मजबूत नियामक निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की आवश्यकता है।

सुभाष चंद्र राठौर (2023) भारत में उच्च शिक्षा के निजीकरण के परिणाम स्वरूप नई शैक्षणिक नीतियां और कार्यक्रम बने हैं जिनसे राष्ट्रीय और स्तर पर रोजगार, आय और आर्थिक विकास के अवसर इस भारतीय शिक्षा प्रणाली में तेजी से बदलाव आया है शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, इस निजीकरण ने व्यक्तियों और समाज दोनों को निजी स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। परिणाम स्वरूप निजी शिक्षण संस्थान प्रतिदिन देश भर में विस्तार कर रहे हैं।

कार्यप्रणाली

वर्तमान अध्ययन के लिये प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा क्षेत्र के यादृच्छिक रूप से चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों में से 5 निजी उच्च शिक्षण तथा 5 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में से 40 नमूने का चयन किया। स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से साक्षात्कार विधि द्वारा डाटा का विश्लेषण किया।

परिणाम और विश्लेषण :

चित्र 1 निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढाँचे को दर्शाता है। परिणाम बताते हैं कि निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढाँचे में अन्तर देखा गया है। प्रतिशत दर्शाता है कि निजी शिक्षण संस्थानों में 60% का बुनियादी ढाँचा सरकारी शिक्षण संस्थानों 40% की तुलना में बेहतर है क्योंकि निजी संस्थानों के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्मार्ट क्लासेस, सुसज्जित कम्प्यूटर लैब, बाई फाई की व्यवस्था, सुसज्जित पुस्तकालय, परिवहन सुविधायें, छात्रावास, खेल के मैदान आदि जैसी बेहतर सुविधायें, प्रदान कर रहे हैं।

चित्र 2 निजी और सरकारी संस्थानों की शिक्षण पद्धति को दर्शाता है। परिणाम बताते हैं कि निजी शिक्षण संस्थानों और सरकारी शिक्षण संस्थानों की शिक्षण पद्धतियों में अन्तर पाया गया है। सरकारी संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक की गुणवत्ता (53%) निजी संस्थानों की शिक्षक की गुणवत्ता (43%) से बेहतर पाये गये हैं। सरकारी संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने आप को अपडेट करने के लिए कई ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं। विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। जबकि निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक की गुणवत्ता और योग्यता के मापदण्डों पर नहीं होती हैं, और उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम विकास वाले कार्यक्रमों का लाभ भी नहीं मिलता है।

चित्र 3 निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले छात्रों के व्यक्तित्व विकास को दर्शाता है। उल्लेखित परिणाम बताते हैं कि निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच व्यक्तित्व विकास में अन्तर पाया गया है। निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के व्यक्तित्व विकास (61%) सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों (39%) की तुलना में व्यक्तित्व विकास बेहतर है, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों अपने छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए अपने संस्थानों में नई-नई कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन करते हैं और साथ पैक्टिकली दुनियाँ से परिचित कराने के लिए शैक्षिक भ्रमण का भी आयोजन करते हैं। क्योंकि आज के समाज की यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है जबकि सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत कम होता है। जिस कारण दोनों शिक्षण संस्थानों के छात्रों के व्यक्तित्व विकास में अन्तर देखने को मिल रहा है।

चित्र 4 निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के छात्रों के सहपाठ्यक्रम गतिविधियों को दर्शाता है। परिणाम बताते हैं कि निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में अन्तर देखा गया है।

प्रतिशत दर्शाता है कि निजी शिक्षण संस्थानों में सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में सम्मिलित (57%) सरकारी शिक्षण संस्थानों (43%) की तुलना में बेहतर है क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के सहपाठ्यक्रम गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

चित्र 5 निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में पठने वाले छात्रों के रोजगार के अवसर को दर्शाता है। उल्लेखित परिणाम बताते हैं कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में पाये जाने वाले छात्रों के बीच अन्तर पाया गया है। परिणाम प्रतिशत दर्शाते हैं कि निजी संस्थानों में (63%) पठने वाले छात्र सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों (37%) से रोजगार के अवसर में बेहतर पायी गयी है क्योंकि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स चलाये जाते हैं। जैसे:- इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एक्टिंग कोचिंग क्लास को कैरिकुलर क्रियायें, नाटक, प्रेजेंटेशन, सेमिनार आदि कोर्स चलाये जाते हैं और उनसे आत्मविश्वास बढ़ता है जिस कारण सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसी सुविधा न मिल पाने के कारण निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों से रोजगार के अवसरों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

निष्कर्ष :

भारत में उच्च शिक्षा में छात्रों की बढ़ती संख्या और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए निजीकरण उच्च शिक्षा संस्थानों ही एक मात्र मार्ग है। जहाँ छात्रों की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। निजीकरण छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में देश और राज्य के बोझ को कम करने का एक मात्र साधन है। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है, कि निजी शिक्षण संस्थान कई क्षेत्रों जैसे- शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, बुनियादी ढाँचा, व्यक्तित्व विकास और रोजगार के अवसर प्रदान में सरकारी शिक्षण संस्थानों से अब तक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्रणाली के निजीकरण से बढ़ती कीमते और खराब गुणवत्ता जैसी कई समस्याएँ जुड़ी हुयी हैं। यह भी देखा गया है कि यदि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर कोई ऐसा नियन्त्रण कार्यकारी प्रणाली की स्थापित कर दिया जाए, तो निजी उच्च शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उच्च शिक्षा के स्तर को केवल सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के बीच सन्तुलन बनाकर ही इस समस्या को सुधारा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अन्वेष्टा और दिलीप (2021) भारत में उच्च शिक्षाका विशेषाधिकार के आई आई टी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट 17 (2) 110&125

गिल (2021) उच्च शिक्षा संस्थानों में परिवर्तनकारी गुणवत्ता अवधारणा पैमाने के विकास और सत्यापन आश्वासन के प्रभाव का अध्ययन] व्यवसाय अनुसंधान रिसर्च पत्रिका 6 (137) 275&287

बेड़ा ओबेरॉय और मनमीत (2017) भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण: आवश्यकता, प्रभाव और सुझाव र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ रिसर्च मैनेजमेंट 8 (3) 15973&15975 आई एस एस एन 0976&3031

मनमीत ओबेरॉय बवेजा (2017) भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण : आवश्यकता, प्रभाव सुझाव,

इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च, 8 (3) 15973 - 15975

मिक्सो स्वेटनेस सिथोले (2024) दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा क्षेत्र पर निजी उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका और प्रभाव : एक व्यापक विश्लेषण, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एण्ड ह्युमन रिसर्च 7 (3) 03 - 19

रोजिब्लोसो मेधी (2018) उच्च शिक्षा के निजीकरण के प्रभाव का अध्ययन विशेषकर कामरूप ग्रामीण जिले के संदर्भ में 3 (9) आई एस एस एन 2456&22165

सुभाष चंद्र राठौर (2023) उच्च शिक्षा में निजीकरण का महत्व : उन्नत सामाजिक अनुसंधान पत्रिका 3 (5)

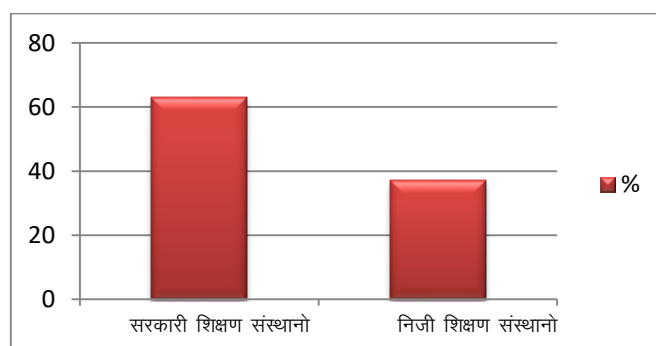
shodhganga.inflibnet.ac.in

<https://wol.iza.org>

<https://pollution.sustainability.derecorg.com>

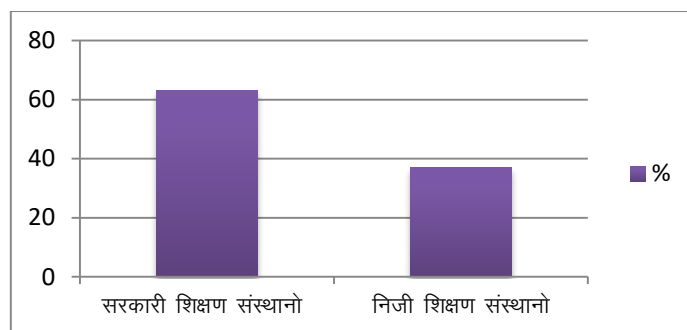
तालिका 1 संकाय गुणवत्ता से संबंधित विवरण तालिका

संकाय गुणवत्ता	%
सरकारी शिक्षण संस्थानो	40
निजी शिक्षण संस्थानो	60



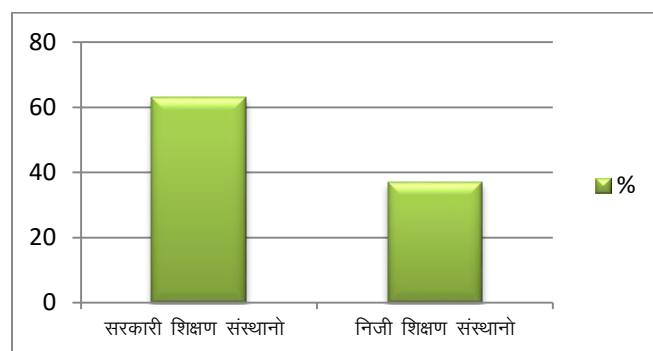
तालिका 2 शिक्षण पद्धति से संबंधित विवरण तालिका

शिक्षण पद्धति	%
सरकारी शिक्षण संस्थानो	53
निजी शिक्षण संस्थानो	43



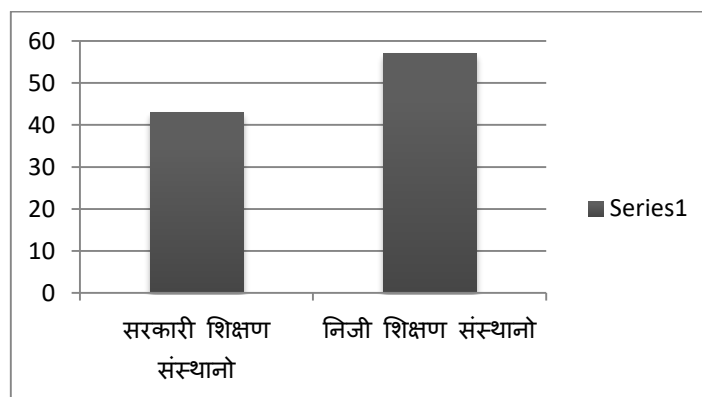
तालिका 3 व्यक्तित्व विकास से संबंधित विवरण तालिका

व्यक्तित्व विकास	%
सरकारी शिक्षण संस्थानो	61
निजी शिक्षण संस्थानो	39



तालिका 4 पठ्यसहगामी क्रियाय से संबंधित विवरण तालिका

पठ्यसहगामी क्रियाय	%
सरकारी शिक्षण संस्थानो	43
निजी शिक्षण संस्थानो	57



तालिका 5 रोजगार के अवसर से संबंधित विवरण तालिका

रोजगार के अवसर	%
सरकारी शिक्षण संस्थानो	63
निजी शिक्षण संस्थानो	37

